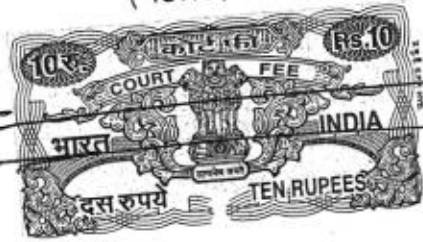


न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा संभाग रीवा

(म०प्र०)



R. 3454-1114

सूर्यबली सिंह तिवारी तनय श्री जगदीश सिंह तिवारी उम्र 50 वर्ष ग्राम

पो० चोरमारी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म०प्र० .....

.....आवेदक / निगराकार

बनाम

.....अनावेदक / गैरनिगराकार

आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959

विरुद्ध आदेश प्रथम निगरानी तहसीलदार रामपुर

बाघेलान प्रकरण. क्र० 38ए68/2003-04 आदेश

दिनांक 25/08/2014 शासन म०प्र० बनाम

सूर्यबली सिंह बगै० निरस्त किये जाने वावत् एवं

अधिनस्थ कोर्ट का रिकार्ड तलब कराया जाय

आवेदक अभिभाषक  
श्री ए.पी. मिश्रा एड.  
व्याय पेश 18.9.14

क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर  
(सर्किट कोर्ट) रीवा

म०प्र० शासन

563  
18.9.14

क्रमांक 3234

रिकार्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक 29-9-14 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदक / निगराकार निगरानी प्रस्तुत कर सादर विनयी

है :-

- 1: यह कि आवेदक / निगराकार ग्राम चोरमारी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म०प्र० का मूल निवासी है।

— आवेदक / निगराकार की आराजी नं० 1601 रकवा 0.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3454-तीन/2014

सूर्यवली सिंह तिवारी

विरुद्ध

म0प्र0 शासन

जिला सतना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश   | पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 2-6-2015         | <p>आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार रामपुर बाघेलान जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 38/ए-68/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 25-08-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।</p> <p>2/ आवेदक ने अपने निगरानी मेमो एवं तर्क में बताया कि आराजी क्रमांक 1601 रकबा 85 डि0 तथा आराजी क्रं 1600/2216/1 रकबा 0.34 डि0 पर उसका मकान बना हुआ है। आवेदक ने निगरानी मेमो के पैरा 4 में आराजी क्रं 1601 एवं 1602 को शासकीय आराजी होना बताया है तथा यह बताया कि सीमांकन किए बिना उसे अतिक्रमण मानकर धारा 248 की कार्यवाही की गई है।</p> <p>3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन के समय आवेदक का शासकीय भूमि पर कब्जा पाये जाने से एवं आवेदक द्वारा शासकीय भूमि से कब्जा नहीं हटाने तथा वर्तमान में अतिक्रमण होने के आधार पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 25-8-2014 के द्वारा संहिता की धारा 248 के तहत सिविल जेल की कार्यवाही हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी की ओर प्रेषित किया है। तहसीलदार के आदेश पत्रिका के अनुसार विवादित भूमि का पूर्व में सीमांकन किया जा चुका है और आवेदक द्वारा शासकीय भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण अग्रिम</p> |  |

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3454-तीन/2014  
सूर्यवली सिंह तिवारी

विरुद्ध

म0प्र0 शासन

जिला सतना

कार्यवाही की जा रही है। तहसीलदार द्वारा पारित उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है।

4/ आवेदक ने विवादित भूमि पर 40 वर्ष से कब्जा होना बताया है। कब्जे के आधार पर स्वत्व प्रदान करने की अधिकारिता व्यवहार न्यायालय को है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्रह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ० मधु खरे)  
सदस्य